लिये उपबन्ध है। उच्चतर व्यावसायिक कर्मचारियों के संबंध में कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष द्वारा चयन समितियां स्थापित की जाती हैं और अन्य वर्गों के लिये, चयन समितियां डीन द्वारा नियुक्त की जाती है।

(ड़) जी नहीं। तथापि, दो कर्मचारियों को, जो सामान्यतः रेलगाड़ी से यात्रा करने के हकदार हैं, कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान से यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।

नियमों के अनुसार, डीन को यह प्राधिकार है कि वे किसी कर्मचारी को प्रत्येक मामले के गुण-दोष का ख्याल रखते हुए उस श्रेणी/साधन से उच्चतर श्रेणी साधन से यात्रा करने की अनुमति दे दें जिसके लिये वह हकदार है। इन दो व्यावसायिक कर्मचारियों के संबंध में, पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी।

Establishment of Medical Research Centres in Rajasthan

2814. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the erstwhile Rajasthan Government approached the Central Government for central assistance for the establishment of a medical research centre which was proposed to be set up by the Bangur Charitable Trust at Jaipur;

(b) whether the Rajasthan Government had accepted a donation of Rs. 25 lakhs collected by the said Charitable Trust;

(c) the Central assistance proposed to be given to it; and

(d) whether the relevant files pertaining to this project are not traceable at the moment and the whole project has been shelved?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) No, Sir.

(b) Yes, the State Government has agreed in principle to accept it.

(c) and (d). In view of the reply to part (a), the question does not arise.

उत्तर प्रदेश में शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना

2815. श्री सुरेन्द्र बिक्रम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या मई और जून, 1977 में उन्हे इस संबंध में किसी संसद् सदस्य का कोई पत्र प्राप्त हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा):(क) कतिपय मानदंडों के अनुसार शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हे विभागीय उपडाकघर बनाया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में अभी तक दो शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। दूसरे प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) और (ग). कानपुर जिले में रूपा विभागेतर शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव एक संसद सदस्य के जरिये मिला है। इस मामले की जांच की जा रही है।